

आयकर संदर्भ

हरबंस सिंह, सी.जे. और बाल राज तुली से पहले, जे.

-रामेश्वर प्रसाद,-----आवेदक,

बनाम

आयकर आयुक्त, दिल्ली-III, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली, -----प्रतिवादी।

1971 का आयकर संदर्भ संख्या 46।

19 फ़रवरी 1973.

आयकर अधिनियम (1961 का XLIII) - धारा 2(43), 210, 212, 218 और 221 - अग्रिम कर - भुगतान न करने पर जुर्माना - क्या धारा 221 के तहत लगाया जा सकता है।

माना गया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 218 की भाषा में, यह स्पष्ट है कि एक निर्धारिती, जो निर्दिष्ट तिथि पर अग्रिम कर की किसी भी किस्त का भुगतान नहीं करता है, जिसे उसे धारा 210 के तहत भुगतान करना आवश्यक है और न ही भेजता है। अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत उसके द्वारा देय अग्रिम कर का अनुमान या संशोधित अनुमान, ऐसी किस्त या किस्तों के संबंध में डिफॉल्ट निर्धारिती माना जाता है। एडवांस टैक्स टैक्स की कोई नई श्रेणी नहीं है। यह वास्तव में नियमित मूल्यांकन से पहले अग्रिम रूप से देय आयकर है और इसलिए अधिनियम की धारा 2(43) में परिभाषित 'कर' के दायरे में आता है। अधिनियम की धारा 221 के तहत कर का भुगतान करने में चूक करने वाले या चूककर्ता माने जाने वाले करदाता पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

आर.ए. में कानून के निम्नलिखित प्रश्न पर राय के लिए 30 अगस्त, 1971 को आयकर न्यायाधिकरण द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 256(1) के तहत दिया गया संदर्भ। क्रमांक 23/71-72 आई.टी.ए. से उत्पन्न। निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिए 1969-70 का क्रमांक 225:-

"क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए धारा 221 के तहत जुर्माना उचित रूप से लगाया गया था?" .

निमो, आवेदक के लिए.

डी.एन.अवस्थी और बी.एस.गुप्ता। प्रतिवादी के लिए वकील।

फैसला

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:- तुली, जे.- आवेदक इस याचिका पर बहस करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ है और न ही उसकी ओर से कोई वकील उपस्थित हुआ है। यह मामला अगस्त, 1972 से दैनिक सूची में है और इसके बावजूद आवेदक ने इस याचिका के अभियोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। परिणामस्वरूप, हमने राजस्व के विद्वान वकील को सुना है निर्णय के लिए हमें भेजे गए प्रश्न का उत्तर देने का आदेश।

(2) निर्धारिती को आदेश के अनुसरण में फॉर्म संख्या 28 में अधिनियम की धारा 210 के तहत अग्रिम कर के भुगतान के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (बाद में अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 156 के तहत मांग का नोटिस जारी किया गया था। आयकर अधिकारी ने दिनांक 28 जुलाई, 1967 को नोटिस दिया। नोटिस 4 सितंबर, 1967 को निर्धारिती को दिया गया। रुपये की पहली किस्त 8,129.00 1 दिसंबर 1967 को देय था, और इतनी ही राशि की दूसरी किस्त 15 मार्च को देय थी। 1968. रुपये की पहली किस्त 8,129.00, जो 1 दिसंबर, 1967 को देय था, निर्धारिती द्वारा भुगतान नहीं किया गया था और अधिनियम की धारा 221(1) के तहत उसे 15 दिसंबर, 1967 को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे 26 दिसंबर, 1967 को कारण बताने की आवश्यकता थी, क्योंकि 8,129.00 रुपये की राशि का भुगतान न करने पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए। 4 जनवरी, 1968 को निर्धारिती को नोटिस दिया गया था, लेकिन रुपये की किस्त। कारण बताओ नोटिस तामील होने के बाद भी उनके द्वारा 8,129.00 रुपये का भुगतान नहीं किया गया और न ही 8,129.00 रुपये का भुगतान न करने पर कोई लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। 24 फरवरी 1968 को उन्हें 6 मार्च 1968 के लिए एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और 27 फरवरी 1968 को निर्धारिती को भेजा गया था, लेकिन उन्होंने न तो कोई जवाब दिया और न ही राशि का भुगतान किया। परिणामस्वरूप निर्धारिती को अधिनियम की धारा 218 के तहत डिफॉल्ट निर्धारिती माना गया और रुपये का जुर्माना लगाया गया। 813.00, जो डिफॉल्ट राशि का 10 प्रतिशत था, 6 मार्च 1968 के आदेश द्वारा लगाया गया था। निर्धारिती ने एक अपील दायर की जिसे 15 अक्टूबर 1969 को अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त ने खारिज कर दिया। निर्धारिती ने फिर एक अपील दायर की आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष, जिसे 23 मार्च 1971 को खारिज कर दिया गया था। अधिनियम की धारा 256(1) के तहत किए गए निर्धारिती के आवेदन पर, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने कानून के निम्नलिखित प्रश्न को राय के लिए इस न्यायालय को भेजा है: —

क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए धारा 221 के तहत जुर्माना उचित रूप से लगाया गया था?

(3) अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष तर्क दिया गया एकमात्र बिंदु यह था कि अग्रिम कर 'कर' नहीं था जैसा कि अधिनियम की धारा 2(43) में परिभाषित किया गया है और इसलिए, निर्धारिती नहीं किया जा सकता है। डिफॉल्ट रूप से निर्धारिती माना जाएगा और अधिनियम की धारा 221 के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। विद्वान न्यायाधिकरण ने एस. नारायणप्पा और ब्रदर्स बनाम आयकर अधिकारी, शहरी सर्कल, बेंगलोर और अन्य (1) में मैसूर उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया, जो भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के तहत एक मामला था, जिसमें यह यह माना गया कि भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 46(1) और (1ए) के प्रावधानों के तहत जुर्माना उस निर्धारिती पर लगाया जा सकता है, जिसने उस अधिनियम की धारा 18ए के तहत मांगे गए अग्रिम कर के भुगतान में चूक की है। श्रीमती में इस मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने विचार किया। कुसुम कुमारी बनाम भारत संघ और अन्य (2) और यह माना गया कि अग्रिम कर के भुगतान में चूक करने वाले निर्धारिती पर अधिनियम की धारा 221 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

“इसमें कोई विवाद नहीं है कि जहां तक अग्रिम कर के अलावा अन्य कर का भुगतान करने में चूक का सवाल है, धारा 221 ऐसे मामलों को कवर करेगी। लेकिन क्या इससे धारा 221 का दायरा खत्म हो जाता है? क्या यह दायरा अग्रिम कर भुगतान में चूक तक भी विस्तारित है? धारा 218 विभिन्न प्रकार के मामलों का वर्णन करती है जब एक निर्धारिती, जिसने अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया है, को डिफॉल्ट माना जाता है। अधिनियम का कोई प्रावधान हमारे सामने नहीं रखा गया है जो यह दर्शाता हो कि ऐसे करदाता से कैसे निपटा जाएगा। धारा 273 में सीमांत नोट है- 'अग्रिम कर का गलत अनुमान या भुगतान करने में विफलता'। लेकिन, जब हम अनुभाग के मुख्य भाग को पढ़ते हैं, तो वहां विचार किया गया जुर्माना निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत अग्रिम कर के असत्य अनुमान और विफलता को संदर्भित करता है। 1 निर्धारिती को अग्रिम कर का अनुमान प्रस्तुत करना होगा। इसमें वह मामला शामिल नहीं है जहां एक निर्धारिती धारा 210 के तहत या उसके द्वारा प्रस्तुत अनुमान पर आयकर अधिकारी द्वारा अपेक्षित अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल रहता है। वे धारा 218 में उल्लिखित मामले हैं।

हमें ऐसा लगता है कि धारा 218 को प्रभावी बनाने के लिए, धारा 221 में अभिव्यक्ति 'कर' को व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए ताकि उसमें अग्रिम कर को भी शामिल किया जा सके। हम बता सकते हैं कि आयकर नियम, 1962 का नियम 38, धारा 210 के तहत एक आदेश के अनुसरण में निर्धारिती को दिए गए अग्रिम कर के संबंध में मांग के नोटिस के रूप का प्रावधान करता है। नोटिस फॉर्म संख्या 28 में है वैधानिक फॉर्म के पैराग्राफ 6 और 7 निर्धारिती को चेतावनी देते हैं कि यदि अग्रिम कर की किस्तों का भुगतान नियत तारीखों पर या उससे पहले नहीं किया जाता है, तो निर्धारिती को ऐसी किस्तों के संबंध में डिफॉल्ट माना जाएगा और धारा के तहत उत्तरदायी होगा। 221 जुर्माना। राजस्व की ओर से, हमें नारायणप्पा एंड ब्रदर्स बनाम आयकर अधिकारी, बेंगलोर (1) (सुप्रा) का मामला भेजा गया है। उस मामले में मैसूर उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि धारा 46(1) और धारा 46(1ए) के तहत जुर्माना लगाने की शक्ति उस निर्धारिती के मामले में नियोजित की जा सकती है जिसने धारा 18ए के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने में चूक की है। याचिकाकर्ता द्वारा यह बताया गया है कि निर्णय धारा 18ए, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 से संबंधित है, और इसे लागू नहीं किया जा सकता है।

नए अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाली स्थिति पर लागू। हमारे लिए उस विवाद के गुण-दोषों पर विचार करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि नए अधिनियम के प्रावधानों पर भी स्थिति वही बनी हुई है।

हमारी राय में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 221, अग्रिम कर के भुगतान में चूक पर लागू होती है। स्वास्तिक इंजीनियरिंग में गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ वर्क्स बनाम आयकर आयुक्त, गुजरात (3) ने यह भी माना कि "अग्रिम कर को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 221 के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से एक कर के रूप में माना जाना चाहिए, और धारा 221 द्वारा अपेक्षित जुर्माना" अधिनियम की धारा 210 के तहत मांगे गए अग्रिम कर के भुगतान में निर्धारिती द्वारा की गई चूक के मामले में अधिनियम लगाया जा सकता है। यदि निर्धारिती निर्दिष्ट तिथि पर अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह डिफॉल्ट होगा, और जब तक इस दायित्व का निर्वहन नहीं होता है, डिफॉल्ट समाप्ति के बाद भी अधिनियम की धारा 221 के अर्थ के भीतर बना रहेगा। वित्तीय वर्ष का।"

हम इन मामलों में विद्वान न्यायाधीशों की टिप्पणियों से सम्मानजनक सहमत हैं और अधिनियम की धारा 218 की भाषा पर हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक निर्धारिती, जो निर्दिष्ट तिथि पर अग्रिम कर की किसी भी किस्त का भुगतान नहीं करता है, जिसकी उसे आवश्यकता होती है। धारा 210 के तहत भुगतान करने के लिए और न ही धारा 212 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत उसके द्वारा देय अग्रिम कर का अनुमान या संशोधित अनुमान भेजता है, ऐसे के संबंध में डिफॉल्ट निर्धारिती माना जाता है। किस्त या किश्तें. एडवांस टैक्स टैक्स की कोई नई श्रेणी नहीं है। यह वास्तव में नियमित मूल्यांकन किए जाने से पहले अग्रिम रूप से देय आयकर है और अधिनियम की धारा 221 के तहत उस करदाता पर जुर्माना लगाया जा सकता है जो कर का भुगतान करने में चूक करता है या चूककर्ता माना जाता है। चूंकि वर्तमान मामले में निर्धारिती 1 दिसंबर, 1967 को देय अग्रिम कर की किस्त का भुगतान करने में विफल रहा, और धारा 212 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत कोई अनुमान या संशोधित अनुमान प्रस्तुत नहीं किया। अधिनियम के अनुसार, उसे उस किस्त के संबंध में डिफॉल्ट रूप से निर्धारिती माना गया था।

(4) विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम की धारा 221 के तहत तत्काल मामले में निर्धारिती पर जुर्माना लगाया जा सकता है जो निम्नानुसार है: -

“221. (1) जब कोई निर्धारिती कर का भुगतान करने में चूक करता है या चूककर्ता माना जाता है, तो उसे धारा 220 की उपधारा (2) के तहत बकाया राशि और देय ब्याज की राशि के अलावा, जुर्माने के रूप में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, एक राशि जो, निरंतर डिफॉल्ट के मामले में, समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है, ताकि, हालांकि, जुर्माने की कुल राशि बकाया कर की राशि से अधिक न हो:

बशर्ते कि ऐसा कोई जुर्माना लगाने से पहले निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

(2) जहां किसी अंतिम आदेश के परिणामस्वरूप कर की राशि, जिसके भुगतान में चूक के संबंध में जुर्माना लगाया गया था, पूरी तरह से कम कर दी गई है, लगाया गया जुर्माना रद्द कर दिया जाएगा और भुगतान की गई जुर्माना की राशि का भुगतान किया जाएगा। वापस किया जाए।”

धारा 220(1) में प्रावधान किया गया है कि धारा 156 के तहत मांग की सूचना में देय अग्रिम कर के अलावा किसी भी राशि का भुगतान स्थान पर नोटिस की सेवा के पैंतीस दिनों के भीतर किया जाएगा और नोटिस में उल्लिखित व्यक्ति को. उप-धारा (2) में प्रावधान है कि यदि धारा 156 के तहत किसी भी मांग नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान उप-धारा (1) के तहत सीमित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो निर्धारिती नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। उप-धारा (1) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के बाद शुरू होने वाले दिन से, और उप-धारा (4) में प्रावधान है कि यदि उप-धारा (1) के तहत सीमित समय के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है या उप-धारा (1) के तहत विस्तारित समय के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है। धारा (3), जैसा भी मामला हो, उक्त नोटिस में उल्लिखित स्थान पर और व्यक्ति को, निर्धारिती को डिफॉल्ट माना जाएगा। इस धारा की भाषा से यह स्पष्ट है कि यह केवल अग्रिम कर के अलावा अन्य राशियों पर लागू होता है। धारा 221(1) अधिनियमित करती है कि धारा 220 की उपधारा (2) के तहत बकाया राशि और देय ब्याज की राशि के अतिरिक्त जुर्माना देय होगा। यह भाषा इस निर्माण को समर्थन देती है कि केवल राशि का भुगतान करने में विफलता अधिनियम की धारा 220 में उल्लिखित धारा 221(1) के तहत दंड की कार्यवाही को आमंत्रित करेगा। धारा का अर्थ यह भी हो सकता है कि एक निर्धारिती, जो डिफॉल्ट में है या जिसे डिफॉल्ट में माना जाता है, धारा 221 में उल्लिखित दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जो बकाया राशि की राशि और उप के तहत देय ब्याज की राशि के अतिरिक्त होगा। -धारा 220 की धारा (2)। प्रश्न यह है कि विधानमंडल के उद्देश्य के अनुरूप होने के कारण किस व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राजस्व के लिए विद्वान वकील ने हमारा ध्यान अधिनियम की धारा 201 की ओर आकर्षित किया है जो यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति, कंपनी या उसका प्रमुख अधिकारी, जैसा कि धारा 191 से 195 में प्रदान किया गया है, जिसे अधिनियम की धारा 194 के तहत आयकर की कटौती करना आवश्यक है, , कटौती नहीं करता है या कटौती के बाद इस अधिनियम के तहत या इसके तहत आवश्यक कर का भुगतान करने में विफल रहता है, कर के संबंध में डिफॉल्ट निर्धारिती माना जाएगा और अधिनियम की धारा 221 के तहत जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन ऐसा करने से पहले जुर्माना लगाया जाता है, तो आयकर अधिकारी को संतुष्ट होना होगा कि ऐसा व्यक्ति या प्रमुख अधिकारी या कंपनी, जैसा भी मामला हो, अच्छे और पर्याप्त कारणों के बिना कर काटने और भुगतान करने में विफल रहा है। ऐसे डिफॉल्ट निर्धारिती पर अधिनियम की धारा 220(2) में कार्रवाई नहीं की जाती है और यदि ऐसे निर्धारिती पर धारा 221 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है, तो यह स्पष्ट है कि धारा 221 के प्रावधान डिफॉल्ट रूप से सभी निर्धारितियों पर लागू होने के लिए थे। या अधिनियम की धारा 201, 218 और 220(4) सहित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत डिफॉल्ट माना जाता है।

इस निष्कर्ष पर पहुंचने वाला एक और संकेत कि अग्रिम कर का भुगतान न करने पर डिफॉल्ट रूप से निर्धारिती पर जुर्माना लगाया जा सकता है, फॉर्म 28 में निहित है जिसमें अग्रिम कर के भुगतान के लिए निर्धारिती को नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस का यह प्रपत्र नियम 38 के तहत निर्धारित है और वैधानिक प्रकृति का है क्योंकि नियम और प्रपत्र अधिनियम की धारा 296 के तहत संसद के सदनों के समक्ष कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखे जाते हैं। करीमथारुवी टी एस्टेट्स लिमिटेड और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य (4) मामले में सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य द्वारा यह माना गया है कि ऐसे नियम ऐसे प्रभावी होते हैं जैसे कि अधिनियम में अधिनियमित किए गए हों। इसलिए, नियम 38 के तहत निर्धारित फॉर्म 28 का प्रभाव ऐसा है मानो यह कानून में ही अधिनियमित किया गया हो। फॉर्म के पैराग्राफ 6 और 7 इस प्रकार पढ़ें:—

“6. यदि धारा 212(1) या (2) के तहत आपके द्वारा देय अग्रिम कर का अनुमान नहीं लगाया गया है, तो आप उस तारीख को या उससे पहले कर की किसी भी किस्त का भुगतान नहीं करते हैं, जैसा कि इस नोटिस के पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट है, यह देय हो जाता है, आपको ऐसी किस्त के संबंध में डिफॉल्टर माना जाएगा और धारा 221 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा देय किस्त की राशि जितनी बड़ी हो सकती है। हालाँकि, यदि आपने धारा 213 के तहत अग्रिम कर के एक हिस्से का भुगतान स्थगित कर दिया है और तदनुसार आयकर अधिकारी को सूचित कर दिया है, तो आपको स्थगन की तारीख तक सश कर के संबंध में डिफॉल्ट में नहीं माना जाएगा।

7. यदि, धारा 212(1) या (2) के तहत आप आयकर अधिकारी को आपके द्वारा देय अग्रिम कर का अनुमान भेजते हैं, लेकिन उचित तिथि पर या उससे पहले उसके अनुसार कर की किसी भी किस्त का भुगतान नहीं करते हैं, तो आप ऐसी किस्त के संबंध में इसे डिफॉल्ट माना जाएगा और धारा 221 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा जो कि किस्त की राशि जितनी बड़ी हो सकती है।

ये दो पैराग्राफ इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि विधानमंडल का इरादा है कि यदि कोई निर्धारिती अग्रिम कर की किसी भी किस्त के भुगतान में चूक करता है, तो वह अधिनियम की धारा 221 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

यह फॉर्म स्पष्ट रूप से अग्रिम कर से संबंधित है और कोई अन्य कर नहीं है और इसलिए, अधिनियम की धारा 221 की व्याख्या के लिए सबसे मजबूत सुराग प्रदान करता है, यानी, यह डिफॉल्ट रूप से या डिफॉल्ट में समझे जाने वाले सभी करदाताओं पर लागू होता है और जुर्माना लगाया जाता है। धारा 221 के तहत लगाया गया जुर्माना अधिनियम की धारा 221 की उप-धारा (2) के तहत उनके द्वारा देय बकाया और ब्याज के अतिरिक्त है।

(5) ऊपर दिए गए कारणों से, राय के लिए हमें भेजे गए प्रश्न का हमारा उत्तर सकारात्मक है, यानी राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के खिलाफ। चूंकि निर्धारिती की ओर से कोई उपस्थिति नहीं है, इसलिए हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

बी.एस.जी.

अवीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्णवादी के सीमित उपयोग के लिए एहैताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णयर्ण का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यावअन्य के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वसुंधरा राव
प्रशिक्षुन्यायिक अधिकारी,
हरियाणा